an>

Title: h Need to improve the standards of teaching and facilities in Government-run educational institutions for higher education in the country and also establish more colleges keeping in view the large number of students seeking admissions in such colleges, particularly in Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : वर्तमान में देश एवं राजधानी दिल्ली की उच्च-शिक्षा व्यवस्था में आयी गिरावट के परिणामस्वरूप अच्छे कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए माध्यमिक बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के बढ़ते दबाव के कारण छात्रों में आत्महत्या की संख्या में वृद्धि चिंताजनक है।

देश में 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जबकि मंत्रालय के अनुसार 2011-12 के दौरान 2.17 करोड़ छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया तथा वर्ष 2012-13 में यह संख्या 2.60 करोड़ हो गई, अर्थात् 43 लाख छात्रों की बढ़ोत्तरी। लेकिन उसी अनुपात में विश्वविद्यालयों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। आज छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। वर्ष 2011-12 में 18-24 वर्ष की आयु के 17.9 प्रतिशत युवा छात्रों ने उच्च शिक्षा पाई, जबकि अमेरिका में यह 33 प्रतिशत है। आज सरकारी विश्वविद्यालयों से कहीं ज्यादा निजी कॉलेज खुल रहे हैं। लगता है कि उदारीकरण और बाजारवाद उच्च-शिक्षा पर भी हावी हो गया है। वर्ष 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 लाख सीटें थीं, जो 2012 में 25 लाख हो गई। भारत की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि कुछ विश्वविद्यालयों में अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता तथा दूसरी ओर हजारों कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्र तैयार नहीं होते।

इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर मारा-मारी व प्रतिस्पर्धा किसी से छुपी नहीं है। पूर्व में लोगों के लिए दाखिला काफी आसान होता था लेकिन आज परिवार की चिंता एडमीशन से ज्यादा ब्रांड की है। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में 89 कॉलेजों में 1,32,435 छात्र नियमित रूप से पढ़ रहे हैं व 2,61,169 छात्र अनौपचारिक रूप से पढ़ रहे हैं। इनमें प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र पड़ोसी राज्यों से दाखिला लेने आते हैं, क्योंकि, यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। पिछले 20 वर्षों में दिल्ली की जितनी जनसंख्या बढ़ी। उसी अनुपात में दिल्ली में कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ी, यह एक चिन्ताजनक विषय है।

अमीर, उच्च एवं मध्य वर्ग के बच्चे नामी-गिरामी संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं या फिर मोटी फीस देकर निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले लेते हैं अथवा विदेश चले जाते हैं लेकिन गरीब का बच्चा कहां शिक्षा ग्रहण करे, इसकी गारंटी कौन सुनिश्चित करेगा?

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब तक छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों की दयनीय स्थिति में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तब तक भारत की उच्च शिक्षा में यही विरोधाभास बना रहेगा। इसके साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं के साथ दिल्ली के छात्रों को भी दाखिले में विकल्प मिल सके।